नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 146
दि. 28.02.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तीन साल बाद अदालत ने पलटा पूरा घटनाक्रम, आबकारी नीति मामले में सभी आरोपी बरी, राजनीति और जांच एजेंसियों की भूमिका पर उठे बड़े सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की राजधानी की राजनीति को हिला देने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे चर्चित कानूनी विवादों में शामिल दिल्ली आबकारी नीति मामला आखिरकार अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जब विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों सहित कुल 23 लोगों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने अपने 598 पृष्ठों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत हजारों पन्नों की चार्जशीट में अपराध का कोई ठोस, विश्वसनीय और कानूनी रूप से स्वीकार्य प्रमाण नहीं मिला। इस फैसले ने न केवल तीन वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत किया, बल्कि देश की राजनीति, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया पर भी व्यापक बहस छेड़ दी है।

यह मामला वर्ष 2022 में सामने आया था, जब दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति_toggle_POLICY को लेकर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगाए गए। आरोप था कि नीति में बदलाव कर कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों और व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और इसके बदले कथित रूप से रिश्वत ली गई। इस मामले की जांच के दौरान कई राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को आरोपी बनाया गया। धीरे-धीरे यह मामला केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया।

जांच एजेंसी ने दावा किया था कि आबकारी नीति में बदलाव एक

सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें नीति निर्माण के दौरान नियमों को जानबूझकर इस प्रकार बदला गया कि कुछ निजी संस्थाओं को लाभ मिले। जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया में कथित तौर पर अवैध धन का लेनदेन हुआ और इस धन का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रस्तुत दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां और विरोधाभास पाए गए।

अदालत ने अपने आदेश में जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि चार्जशीट में प्रस्तुत तथ्यों और गवाहों के बयानों के बीच स्पष्ट असंगति है और कई महत्वपूर्ण आरोप केवल अनुमान और परिस्थितिजन्य आधार पर लगाए गए थे। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य आवश्यक होते हैं और केवल संदेह या संभावना के आधार पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता।

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू यह था कि इसमें देश की राजधानी के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और वे लगभग डेढ़ वर्ष तक जेल में रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने भी कई महीनों तक हिरासत में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने जेल से ही अपनी पार्टी और सरकार का संचालन किया, जो भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व स्थिति थी।

इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक प्रभाव भी गहरा रहा। आम आदमी पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अपनी पहचान बनाई थी, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में आ गई। पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान हुआ और कई चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विरोधियों ने इस मामले को लेकर पार्टी और उसके नेताओं पर तीखे हमले किए और इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।

अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों तक उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः अदालत ने सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने न्याय और सत्य पर विश्वास बनाए रखा।

इस मामले ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में कई कमियां थीं और प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस टिप्पणी ने देश में जांच एजेंसियों की भूमिका और उनकी जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का प्रभाव केवल कानूनी या प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। इससे आम आदमी पार्टी को अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है और पार्टी इस फैसले को अपनी नैतिक और राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। वहीं दूसरी ओर, इस फैसले ने राजनीतिक विरोधियों की रणनीति और आरोपों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

अफ्रीका में सूरत के उद्योग जगत की दस्तक, घाना और केन्या दौरे से खुलेंगे अरबों के निवेश और व्यापार के नए द्वार

(जीएनएस)। सूरत। दक्षिण गुजरात के औद्योगिक परिदृश्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने 14 से 21 फरवरी 2026 के दौरान अफ्रीकी देशों घाना और केन्या का एक उच्च स्तरीय बिज़नेस डेलीगेशन दौरा आयोजित किया। इस दौरे का उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, नए निवेश अवसरों की पहचान करना और दक्षिण गुजरात के उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ना था। इस यात्रा ने न केवल व्यापारिक संभावनाओं के नए रास्ते खोले, बल्कि भविष्य में बहु-अरब रुपये के निवेश और सहयोग की मजबूत नींव भी रखी। इस हाई-लेवल डेलीगेशन में SGCCI के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, SGCCI ग्लोबल कनेक्ट के सीईओ परेश भट्ट, सीनियर एजीक्यूटिव मानसी पटने सहित विभिन्न क्षेत्रों के 13 प्रमुख उद्योगपति शामिल थे। ये प्रतिनिधि इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वॉटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गोल्ड और डायमंड, आईसीटी, हाइजीन प्रोडक्ट्स तथा हेवी माइनिंग इक्विपमेंट जैसे विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस विविधता ने दौरे को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया और कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को मजबूत किया।

डेलीगेशन का पहला पड़ाव घाना का कोनांगो शहर रहा, जहां असांते अकिम सेंट्रल म्युनिसिपल असेंबली के मेयर एबेनेज़र एकोव ऐडू के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में स्थानीय औद्योगिक विकास, निवेश अवसरों और भारतीय उद्योगों की भागीदारी पर चर्चा की गई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने कुमासी और राजधानी अकरा का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों और स्थानीय उद्योगपतियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं।

अकरा में घाना फ्री ज़ोन अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित हाई-लेवल मीटिंग में निवेश और औद्योगिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा कई बी2बी (बिज़नेस-टू-बिज़नेस) मीटिंग्स भी आयोजित की गईं, जिनमें भारतीय और घाना के उद्योगपतियों के बीच सीधे संवाद हुआ। इन बैठकों ने व्यापारिक साझेदारी के नए अवसरों को जन्म दिया और भविष्य में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं को मजबूत किया।

इस दौरे का एक महत्वपूर्ण परिणाम घाना नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ हस्ताक्षरित एमओयू रहा, जिससे दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग को संस्थागत रूप मिला। इसके अतिरिक्त मदीना चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी सहयोग को लेकर समझौता किया गया, जो व्यापारिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

डेलीगेशन ने केन्या में भी कई महत्वपूर्ण स्थलों और परियोजनाओं का दौरा किया। उन्होंने वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट्स, जिराफ सेंटर और सस्टेनेबल टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और वहां की संरक्षण एवं पर्यटन नीतियों की जानकारी प्राप्त की। इससे भारतीय उद्योगपतियों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को समझने का अवसर मिला।

इस दौरे में शामिल उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और व्यापार की संभावनाएं व्यक्त कीं। अशोक जीरावाला ने इस यात्रा को अत्यंत सफल बताते हुए कहा कि इससे भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंधों को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में इस सहयोग से दोनों देशों के उद्योगों को व्यापक लाभ मिलेगा।

निएनम जेम्स की प्रतिनिधि हेमलता लोहार ने घाना के गोल्ड ट्रेड इकोसिस्टम को पारदर्शी और व्यवस्थित बताते हुए लगभग 400 करोड़ रुपये के संभावित व्यापार की संभावना जताई। डिटॉक्स ग्रुप के वरुण कॉन्ट्रैक्टर ने पर्यावरण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 250 से 300 करोड़ रुपये के निवेश अवसरों का उल्लेख किया। किसुकी हेल्थकेयर LLP के मयूर अग्रवाल ने लगभग 150 करोड़ रुपये के व्यापार की संभावना के साथ घाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना साझा की।

डेसर तालुका को बाल विवाह और नशा मुक्त बनाने की पहल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया विशेष

(जीएनएस)। वडोदरा। समाज के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वडोदरा जिले के डेसर तालुका को बाल विवाह मुक्त और नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। यह कार्यक्रम 100 दिवसीय थीम आधारित अभियान के तहत शुक्रवार को डेसर स्थित तालुका सेवा सदन में संपन्न हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना है, बल्कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर रखकर एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करना भी है।

कार्यक्रम का आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय और मिरेकल फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस प्रशिक्षण में डेसर तालुका के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल अधिकारों, बाल सुरक्षा कानूनों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण सत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को विशेष रूप से समझाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह के कारण विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा बाधित हो जाती है और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया गया। उन्हें यह बताया गया कि यदि किसी गांव में बाल विवाह की संभावना या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके और बाल विवाह को रोका जा सके।

प्रशिक्षण में बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आज के समय में नशे की समस्या समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है और इसका प्रभाव बच्चों और युवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। नशे की लत बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सकती है और उन्हें अपराध तथा सामाजिक समस्याओं की ओर धकेल सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग मिलकर इस समस्या के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करें।

जिला प्रशासन द्वारा डेसर तालुका को परिवार सशक्तिकरण से जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी चुना गया है। इस परियोजना के तहत परिवारों को जागरूक करने, बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी अमित वसावा, मिरेकल फाउंडेशन के प्रतिनिधि जयेशभाई मुंधवा, सीडीपीओ हिनाबेन और संरक्षण अधिकारी जितेंद्र मेहरिया सहित कई अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने गांवों में जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और नशे के खतरे के बारे में जागरूक करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि समाज के सभी लोग मिलकर प्रयास करें, तो बाल विवाह और नशे जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न केवल कानूनी और सामाजिक जानकारी प्रदान की गई, बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी किया गया। यह पहल निश्चित रूप से डेसर तालुका को बाल विवाह और नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

जिला प्रशासन को विश्वास है कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित, स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य मिल सकेगा।

ऊर्जा के भविष्य की तैयारी: बढ़ती मांग के बीच गुजरात में मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की चुनौती और अवसर

(जीएनएस)। अहमदाबाद। औद्योगिक प्रगति, शहरी विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेज़ी से बढ़ते कदमों के बीच गुजरात आने वाले दशक में बिजली की मांग में ऐतिहासिक वृद्धि देखने जा रहा है। विशेषज्ञों और सरकारी अनुमानों के अनुसार वर्ष 2034-35 तक राज्य की पीक बिजली मांग 35,000 मेगावाट से अधिक पहुंच सकती है, जो वर्तमान स्तर से लगभग 70 प्रतिशत अधिक होगी। यह अनुमान सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य को लेकर विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस तेजी से बढ़ती मांग ने राज्य के सामने न केवल उत्पादन बढ़ाने, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने की चुनौती खड़ी कर दी है।

वर्तमान समय में गुजरात देश के सबसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में शामिल है, जहां मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और डेटा सेंटर जैसे कई सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहे हैं। नए औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब और बंदरगाह आधारित उद्योगों के विकास ने बिजली की खपत में लगातार वृद्धि की है। वर्ष 2023-24 में राज्य की पीक बिजली मांग लगभग 20,964 मेगावाट दर्ज की गई थी, लेकिन आने वाले वर्षों में यह मांग लगभग दोगुनी होकर 35,000 मेगावाट के स्तर तक पहुंच सकती है। इसी अवधि में राज्य की वार्षिक बिजली खपत भी 240 बिलियन यूनिट से अधिक होने का अनुमान है, जो वर्तमान खपत से काफी अधिक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। असली चुनौती इस बिजली को उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता केंद्रों तक सुरक्षित, तेज़ और कुशल तरीके से पहुंचाने की है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार,

यदि ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत नहीं होगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद कमजोर ट्रांसमिशन लाइनों के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित होती है या अतिरिक्त बिजली का उपयोग नहीं हो पाता।

गुजरात में ऊर्जा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोलर और विंड ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। अनुमान है कि वर्ष 2034-35 तक राज्य की कुल अनुबंधित बिजली क्षमता का लगभग दो-तिहाई हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से आएगा। यह पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ेगा।

समस्या यह है कि जहां नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, वे क्षेत्र औद्योगिक और शहरी केंद्रों से काफी दूर हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और दक्षिण गुजरात जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की मांग सबसे अधिक है, जबकि उत्पादन केंद्र कच्छ और सौराष्ट्र में स्थित हैं। ऐसे में लंबी दूरी तक बिजली को सुरक्षित और बिना नुकसान के पहुंचाने के लिए उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों और आधुनिक ग्रिड सिस्टम की आवश्यकता होगी।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क बिजली प्रणाली की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। यदि यह मजबूत नहीं होगा तो पूरी ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मजबूत ट्रांसमिशन सिस्टम न केवल बिजली की आपूर्ति को स्थिर बनाता है, बल्कि यह ऊर्जा की लागत को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा, यह विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आने वाले वर्षों में गुजरात को ऊर्जा भंडारण यानी बैटरी स्टोरेज सिस्टम में भी बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि राज्य को 10 गीगावाट से अधिक बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करनी पड़ सकती है। यह स्टोरेज सिस्टम सौर और पवन ऊर्जा जैसे अस्थिर स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संग्रहित करने और जरूरत के समय उपयोग करने में मदद करेगा। लेकिन यह तभी प्रभावी होगा जब ट्रांसमिशन नेटवर्क पर्याप्त मजबूत और आधुनिक होगा।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को हाईवे, रेलवे और बंदरगाहों की तरह ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए नए हाई-कैपेसिटी ट्रांसमिशन कॉरिडोर का निर्माण, पुराने सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण, नई तकनीकों का उपयोग और राइट ऑफ वे से जुड़ी समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इसके अलावा, स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बढ़ावा देना होगा ताकि बिजली की आपूर्ति अधिक कुशल और विश्वसनीय बन सके।

गुजरात सरकार और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में कई कदम उठा रही हैं। राज्य पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी रहा है और अब ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यदि यह प्रयास सफल होते हैं, तो गुजरात न केवल अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आने वाला दशक गुजरात के लिए निर्णायक साबित होगा। यदि राज्य समय रहते ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने में सफल होता है, तो वह न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा, बल्कि स्वच्छ और सस्ती बिजली के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। लेकिन यदि इस दिशा में पर्याप्त निवेश और योजना नहीं बनाई गई, तो बढ़ती मांग और उत्पादन क्षमता के बावजूद बिजली आपूर्ति में बाधाएं आ सकती हैं।

इस प्रकार, गुजरात के ऊर्जा भविष्य की सफलता केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एक मजबूत, आधुनिक और कुशल ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण पर निर्भर करेगी। यही नेटवर्क राज्य की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संतुलित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर और मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संपादकीय

न्यायिक तंत्र में संवेदना करुणा को तरजीह

भारतीय समाज में किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिये न्याय पाने की प्रक्रिया में न्यायिक तंत्र की विसंगतियों से जूझना कष्टप्रद रहा है। समाज में सोच रही है कि पहले ही हिंसा का शिकार हुई स्त्री द्वारा अपनी आपबीती को बार-बार दोहराना पुनः उसी यंत्रणा से गुजरना जैसा होता है। उसकी अभिव्यक्ति की गोपनीयता व पहचान सुरक्षित रखने की भी जरूरत महसूस की जाती रही है। विडंबना यह भी रही है कि अक्सर स्त्री के खिलाफ हुई हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक धारणाओं पर पितृसत्तात्मक सोच वाली मानसिकता का वर्चस्व रहता है। निर्विवाद रूप से हर तरफ से हारा-हताश व्यक्ति न्याय की चौखट पर अंतिम सहारे के रूप में जाता है। लेकिन कई बार देखने में आया है कि स्त्री के विरुद्ध हुए अपराध के मुकदमे के दौरान टिप्पणियों व फैसले पर पूर्वाग्रहों का असर नजर आता है, जिसे पहले से पीड़ित स्त्री के कष्ट में इजाफा ही होता है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में यदा-कदा संवेदनशीलता व करुणा का भाव नदारद पाया गया। यही वजह है कि समय-समय पर शीर्ष अदालत ने न्यायाधीशों के निर्णयों को रूढ़िवादिता के प्रभाव से मुक्त करने के लिये प्रयास किए हैं। इसी आलोक में पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को यौन हिंसा व स्त्री से जुड़े अन्य अपराधों के परिप्रेक्ष्य में जजों तथा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए संवेदनशीलता तथा करुणा विकसित करने की पहल की है। दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। निस्संदेह, इस संवेदनशील पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का यह प्रयास भविष्य में नई लीक बनाएगा, जिसमें न्यायाधीश स्त्री के विरुद्ध यौन हिंसा व अन्य अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ सुनवाई कर सकेंगे। इसके साथ ही संभव हो सकेगा कि उनके फैसलों पर किसी सामाजिक भेदभाव की धारणा व पूर्वाग्रह का असर नजर न आए।

निस्संदेह, इस प्रयास से न्याय को अधिक मानवीय व संवेदनशील बनाने में मदद मिल सकेगी। विगत में भी इस दृष्टिकोण की कमी न्यायिक प्रक्रिया में महसूस की जाती रही है। कई तरह की विसंगतियों को कई फैसलों में महसूस किया जाता रहा है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत को न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता विकसित करने की जरूरत पर बल दिया गया। हमारे समाज में न्यायाधीशों को पंच-परमेश्वर की संज्ञा दी गई है और उनसे नीर-क्षीर विवेक के साथ संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद की जाती रही है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद न्यायपालिका के नजरिये में बदलाव के साथ न्यायिक प्रक्रिया में निहित संवेदनशीलता का समावेश हो सकेगा। वैसे तो विगत में भी इस दिशा में कई रचनात्मक पहल की गई हैं, लेकिन उनके आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसा ही एक प्रयास साल 2023 में एक पुस्तिका के रूप में सामने आया था, जिसमें फैसलों में पुरुष प्रधान मानसिकता वाली शब्दावली से परहेज करने का सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही विगत में न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिये लैंगिक संवेदनशीलता पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है। एक अन्य विकल्प के रूप में न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत भी बतायी जाती रही है। दरअसल, एक विसंगति यह भी रही है कि देश की निचली अदालतों में महिलाओं से जुड़े यौन हिंसा व अन्य गंभीर अपराधों के मामले में फैसले देते वक्त सामाजिक यथार्थ की अवहेलना की जाती रही है। फलस्वरूप कानूनी प्रावधानों की व्याख्या में चूक से अपराध की प्रकृति कमतर आंकी जाती है। जिससे पीड़ित महिला की न्याय की डगर मुश्किलों भरी हो जाती है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को लैंगिक संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाए जाने के बाद पीड़िताओं को वास्तविक न्याय मिल सकेगा। तब न्यायाधीश पितृसत्तात्मक दुराग्रहों से निरपेक्ष रहकर महिला के वास्तविक कष्टों को महसूस करते हुए प्राकृतिक न्याय दे सकेंगे। भारत में 21वीं सदी के उन्नत सामाजिक परिवेश में लैंगिक संवेदनशीलता वाला न्याय एक अपरिहार्य स्थिति है। शीर्ष अदालत के इस दिशा में प्रयास वक्त की जरूरत के अनुरूप ही हैं।

लोकतंत्र के मंदिर में गरिमापूर्ण आचरण जरूरी

> "जनतंत्र संवाद के माध्यम से चलता है। देश के मतदाता ने सरकार को ही नहीं चुना, विपक्ष को भी चुना है। इसलिए दोनों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। आज विडंबना यह भी है कि विपक्ष न बोलने देने की शिकायत कर रहा है।

लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। संभवतः मार्च के दूसरे सप्ताह में सदन में इस पर बहस होगी और लोकसभा में सरकारी पक्ष और विपक्ष के गणित को देखते हुए यह लगभग तय है कि प्रस्ताव अस्वीकृत ही होगा, पर सदन में इस तरह का प्रस्ताव आना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीकर ओम बिरला पर विपक्ष ने पक्षपातपूर्ण आचरण और नेता प्रतिपक्ष को न बोलने देने का आरोप लगाया है।

यह पहली बार नहीं है कि हमारी लोकसभा में अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगा है। अब तक तीन बार इस आशय के प्रस्ताव सदन में रखे गये हैं। वस्तुतः पहली लोकसभा में ही सन् 1954 में तत्कालीन अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया था। फिर 1966 और 1987 में ऐसा प्रस्ताव रखा गया। तीनों ही बार यह प्रस्ताव संख्याबल के आधार पर खारिज हो गया था। पर यह बात अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि लोकसभा के सदस्यों ने अपने विवेक के आधार पर ऐसा प्रस्ताव रखना ज़रूरी समझा था।

जब पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ इस आशय का प्रस्ताव आया तो 479 सदस्यों वाले सदन में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 364 सदस्य थे। प्रस्ताव का अस्वीकृत होना स्पष्ट था। जब इस पर बहस हुई तो उपाध्यक्ष ने दो घंटे का समय निर्धारित किया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उपाध्यक्ष से आग्रह किया था कि सत्तारूढ़ पक्ष को कम बोलना स्वीकार होगा, आप विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए अधिकाधिक समय दें! देश के प्रथम प्रधानमंत्री का यह कथन हमारी जनतांत्रिक परंपरा का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम आज की स्थिति को देखते हैं, तो कुछ हैरानी होना स्वाभाविक है

और कुछ पीड़ा का अनुभव करना भी। आज विपक्ष का आरोप है कि उसे सदन में बोलने नहीं दिया जाता।

जनतंत्र संवाद के माध्यम से चलता है। देश के मतदाता ने सरकार को ही नहीं चुना, विपक्ष को भी चुना है। इसलिए दोनों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। आज विडंबना यह भी है कि विपक्ष न बोलने देने की शिकायत कर रहा है।

बहरहाल, सदन में एक अराजकता-सी स्थिति पैदा हो गयी है। यह स्थिति बदलनी ही चाहिए और इसका एकमात्र उचित तरीका यह है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे का सम्मान करने की जनतांत्रिक परंपरा का निर्वाह करें। जब सदन में बात करने का अवसर नहीं मिलता तो बात सड़क पर होती है। कई बार यह बात बहुत आगे बढ़ जाती है। दिल्ली में कृत्रिम मेधा के वैश्विक सम्मेलन में स्थिति कुछ ऐसे ही हो गयी थी जब कांग्रेस के दस-बीस कार्यकर्ता अपनी टी-शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन यह रूप न लेता तो अच्छा था, पर ऐसा भी नहीं है कि इस प्रदर्शन से कोई पहाड़ टूट पड़ा है। दुनिया भर में, हमारे देश में भी, अक्सर विपक्ष ऐसे प्रदर्शन करता रहा है। वस्तुतः विरोध-प्रदर्शन जनता की व्यवस्था का एक जायज अधिकार है और इस तरह के प्रदर्शनों से कोई देश शर्मसार नहीं होता।

वे और बातें हैं जिनसे कोई देश शर्मिंदा होता है, या उसे शर्मिंदा होना चाहिए। जब देश के अस्सी करोड़ लोग अपना पेट भरने के लिए सरकार के मुफ्त अनाज पर निर्भर करते हैं, तब देश शर्मिंदा होता है। जब देश में युवाओं की बेरोज़गारी के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ने लगता है, तब देश को शर्म आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत की एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार आज देश के 83 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों में स्नातकों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है। सरकारी संस्थानों में चपरासी के पद के लिए स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्र आवेदन कर रहे हैं। इस तरह के तथ्य किसी देश को शर्मिंदा करते हैं। टी-शर्ट उतारने से बात नहीं बिगड़ती। टी-शर्ट तो हमारे क्रिकेट कप्तान ने भी तब उतारी थी जब इंग्लैंड में हमारी टीम ने विजय प्राप्त की थी। यह अपना उत्साह या अपनी हताशा प्रकट करने का भी एक तरीका होता है। इसे नंगई कहना ग़लत है। हैरानी तो तब होती है जब देश का शीर्ष नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में हल्की भाषा का उपयोग करता है। एक जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने कहा था कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिक अवसर मिलना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सदन में विपक्ष की संख्या बहुत कम है, इसलिए सत्तारूढ़ कांग्रेस के सांसदों को जागरूक रहकर विपक्ष की भूमिका भी निभानी चाहिए, ताकि सरकार व्यर्थ का गर्व न करने लगे। यह व्यर्थ का गर्व किसी भी शासक के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। गर्व की जगह घमंड शब्द काम में लें तो बात आसानी से समझ आ जाती है।

एक बात और है जिसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ रखा गया अविश्वास का प्रस्ताव भले ही संख्या-बल को देखते हुए सफल न हो पाये, पर किसी अध्यक्ष के खिलाफ 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार' का आरोप लगना भी अपने आप में अफसोस की बात ही होती है। लोकसभा में एक लंबे अर्से से सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा। विपक्ष द्वारा मचाये जाने वाले शोर-शराबे से किसी को एतराज हो सकता है, पर जनतांत्रिक परंपराओं का तकाज़ा है कि नेता विपक्ष को बोलने न देने के आरोप को गंभीरता से लिया जाये। नेता विपक्ष सामान्य सदस्य नहीं होता, जहां उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष का भी दायित्व बनता है कि वह नेता प्रतिपक्ष की महत्ता को समझे।

लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार से सभी पक्षों का विश्वास जीतेंगे। इसी तरह सत्तारूढ़ पक्ष के सांसदों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे। पिछले एक अर्से में कई सदस्यों का व्यवहार शालीनता और जिम्मेदारी की सीमाओं का अतिक्रमण करता दिखता है। यह सही है कि सांसदों को यह अधिकार है कि वह संसद में कुछ भी कह सकते हैं, पर इस 'कुछ भी' पर पीठासीन अधिकारियों और स्वयं उनके विवेक का नियंत्रण रहना ही चाहिए। देश को यदि शर्मिंदा होना है तो इस अनियंत्रित व्यवहार पर होना चाहिए। संसद ही नहीं, हमारे मंत्री भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते दिखे हैं। शर्म इस उल्लंघन पर आनी चाहिए।

हमारे नेता 'नंगई' शब्द का उपयोग किस अर्थ और किस संदर्भ में करते हैं, वे ही जानें, पर उन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि उनका व्यवहार और उनके द्वारा उच्चारे गये शब्द किसी भी दृष्टि से घटिया न लगें। जब कभी ऐसा लगता है, शर्म आती है हमें। देश ऐसी ही बातों से शर्मिंदा होता है।

प्रेरणा

आशीर्वाद की प्रतीक्षा से नहीं, प्रयास की शुरुआत से बदलता जीवन

एक पुराने नगर की संकरी गलियों में रहने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था, और हर दिन उसके लिए संघर्ष लेकर आता था। वह अक्सर सोचता कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका जीवन बदल जाए। उसे लगता था कि उसकी असफलता का कारण उसका दुर्भाग्य है, और अगर किसी महान संत का आशीर्वाद मिल जाए तो उसका भाग्य पलट सकता है। इसी आशा के साथ वह नगर के बाहर रहने वाले महान संत और दार्शनिक सुकरात के पास जाने लगा।

वह जब भी उनके पास जाता, उनके चरणों में बैठ जाता और हाथ जोड़कर विनती करता, "गुरुदेव, मुझे संपन्नता का आशीर्वाद दीजिए। मेरे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए।" उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उसके भीतर कर्म की कोई तैयारी नहीं थी। वह चाहता था कि बिना कुछ किए उसका जीवन बदल जाए। संत उसे ध्यान से देखते, उसकी बात सुनते, और फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा शुरू कर देते। वे उसे ज्ञान की बातें बताते, जीवन का अर्थ समझाते, लेकिन उसे संपन्नता का आशीर्वाद नहीं देते।

यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। वह व्यक्ति हर दिन नई उम्मीद के साथ आता, लेकिन हर बार निराश होकर लौट जाता। धीरे-धीरे उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर संत उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे। उसे लगता था कि शायद संत उसकी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। लेकिन सच्चाई यह थी कि संत उसकी पीड़ा को भली-भांति समझते थे, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

समय बीतता गया और उस व्यक्ति की स्थिति और भी कठिन होती गई। अब उसके पास अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं बचे थे। वह दिनभर इधर-उधर भटकता, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर लौटता, तो उसके चेहरे पर थकान और मन में निराशा होती। एक दिन उसने बाजार में देखा कि लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कपड़े, कोई अनाज। सभी मेहनत कर रहे थे, और उनके चेहरों पर संतोष दिखाई दे रहा था।

उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने सोचा कि अगर ये लोग मेहनत करके अपना जीवन चला सकते हैं, तो वह क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि वह भी कोई छोटा काम शुरू करेगा। उसने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और कुछ फल खरीद लिए। उसने उन फलों को एक टोकरी में सजाया और बाजार की ओर चल पड़ा।

शुरुआत में उसे बहुत संकोच हुआ। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने ग्राहकों को आवाज लगानी शुरू की। कुछ लोग उसके पास आए, फलों को देखा, और खरीद लिया। दिन के अंत में जब उसने अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथ में ली, तो उसके मन में एक नई भावना जागी। यह भावना आत्मविश्वास की थी, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी।

अब वह रोज बाजार जाने लगा। हर दिन उसकी मेहनत बढ़ती गई और उसके साथ-साथ उसका आत्मविश्वास भी। उसने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने में एक अलग ही संतोष होता है। अब वह पहले की तरह भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि अपने कर्म पर विश्वास करने लगा था।

एक दिन जब वह फलों की टोकरी लेकर बाजार जा रहा था, तभी सामने से संत सुकरात आते दिखाई दिए। संत ने उसे देखा और उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, "तुम्हारा जीवन समृद्ध हो, तुम्हारे प्रयास सफल हों, और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए।" यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया।

उसने तुरंत संत के चरणों में झुककर कहा, "गुरुदेव, मैं तो इतने समय से आपसे यही आशीर्वाद मांग रहा था, लेकिन आपने कभी नहीं दिया। आज आपने स्वयं मुझे आशीर्वाद क्यों दिया?"

संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "पहले तुम केवल आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे, कर्म करने के लिए तैयार नहीं थे। बिना कर्म के आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं होता। आशीर्वाद केवल उस व्यक्ति के जीवन में फलता है, जो अपने प्रयास से उसे फलने योग्य बनाता है। अब तुमने अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाई है। अब तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारे आशीर्वाद को सफल बनाएगा।"

उनके शब्द सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक नई समझ पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक गलत दिशा में सोच रहा था। वह आशीर्वाद को सफलता का कारण मान रहा था, जबकि सच्चाई यह थी कि सफलता का कारण परिश्रम होता है, और आशीर्वाद केवल उस परिश्रम को शक्ति देता है।

उस दिन के बाद उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल भाग्य या आशीर्वाद पर निर्भर नहीं था। वह जान चुका था कि उसका भविष्य उसके अपने हाथों में है। उसने अपने काम को और अधिक ईमानदारी और लगन से करना शुरू किया। धीरे-धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। उसकी आय बढ़ी, उसका आत्मविश्वास मजबूत हुआ, और उसका जीवन स्थिर होने लगा।

अब जब भी वह संत से मिलता, वह उनसे आशीर्वाद नहीं मांगता था। वह केवल उनका धन्यवाद करता था, क्योंकि उन्होंने उसे सबसे बड़ा सत्य सिखाया था—कि आशीर्वाद तभी फलता है, जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्म से उसे फलने योग्य बनाता है।

उसकी कहानी अब नगर के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझने लगे कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाता है। आशीर्वाद केवल एक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को दिशा देने का काम व्यक्ति के अपने कर्म करते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति ने यह सीख लिया कि सच्ची संपन्नता बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के साहस और परिश्रम को पहचान लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में बदलता है।

इंसेफ्लाइटिस पर निर्णायक विजय

एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सफलता हाल के समय की सबसे उल्लेखनीय जनस्वास्थ्य उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कठोर क्रियान्वयन क्षमता ने राज्य को 2017 में 5,400 से अधिक मामलों और 650 से अधिक मौतों से 2024 में मामलों में तीव्र गिरावट और शून्य मृत्यु तक पहुंचा दिया। यह एक ऐसी सफलता है जो कभी भारत के सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांकों से जकड़े राज्य के खाते में गई है।

चार दशकों तक इंसेफ्लाइटिस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रखा था। गोरखपुर इसका केंद्र रहा, जबकि कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिले इसकी चपेट में रहे। यह बीमारी बच्चों और युवाओं को अचानक तेज बुखार और मानसिक भ्रम के साथ जकड़ लेती थी, जो अक्सर मौत का कारण बन जाती थी। जो बच जाते, वे जीवनभर न्यूरोलाजिकल और शारीरिक अक्षमता से पीड़ित रहते। वर्ष 2017 तक इस बीमारी ने लगभग 50 हजार जानें ले लीं, जिनमें अधिकांश बच्चे थे। यह आंकड़ा न केवल चिकित्सा विफलता, बल्कि दशकों की प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का प्रतीक था। दूषित पानी, कुपोषण, गंदगी और अस्वच्छ जीवन स्थितियों ने संक्रमण को बढ़ावा दिया, ऊपर से पूरी तरह से जर्जर स्वास्थ्य ढांचे ने हालात को काफी गंभीर बना दिया था। राज्य में तब बच्चों के लिए आईसीयू का अभाव, कमजोर लैब सुविधाएं, अपर्याप्त एंबुलेंस सेवाएं आम बात थीं। यही कारण था कि 2017 तक 28 जिले लगातार संक्रमित रहे और इंसेफ्लाइटिस राज्य की विफलता का प्रतीक बन गया। इसी पृष्ठभूमि में 2017 के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन प्राथमिकता बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इसे मिशन मोड पर लिया गया। चुनौती केवल बीमारी से लड़ने की नहीं थी, बल्कि भरोसेमंद स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने की भी थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी बिखरे हुए हस्तक्षेप या संकट-प्रतिक्रिया तंत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि केंद्र की सतत निगरानी, संसाधन आवंटन, विभागीय समन्वय और रणनीतिक नेतृत्व पर आधारित एक व्यापक और व्यवस्थित सुधार कार्यक्रम था। सात विभागों को जोड़कर समग्र योजना बनी। वर्ष 2019 में गोरखपुर में एम्स की स्थापना, आइसीएमआर की भूमिका मजबूत हुई। सक्रिय सर्वेक्षण से इंसेफ्लाइटिस के कारणों और जोखिमों की पहचान हुई, लैब अपग्रेड हुए, डायग्नोस्टिक किट विकसित हुईं। बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर को उन्नत किया गया, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बने, एंबुलेंस सेवाएं शुरू हुईं। बुखार-ट्रैकिंग सिस्टम ने इंसेफ्लाइटिस की शुरुआती पहचान को संभव बनाया। व्यापक टीकाकरण अभियान ने जेई वायरस के प्रसार को रोका। वर्ष 2018 में बीआरडी मेडिकल कालेज में बाल पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ, जिससे दिव्यांग बच्चों को दीर्घकालिक देखभाल मिली।

अस्पतालों से परे असली सफलता जीवन स्तर और स्वच्छता सुधार से मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजनाएं सटीकता से लागू हुईं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बने, जल जीवन मिशन से नल से जल कनेक्शन दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संक्रामक रोग अभियान चला, पोषण अभियान से बच्चों एवं माताओं को पोषण दिया गया और आयुष्मान केंद्रों एवं आरोग्य मेले से मुफ्त इलाज किया गया। इन सुधारों ने सीधे तौर पर कुपोषण, असुरक्षित पानी और खराब स्वच्छता जैसी जड़ों पर चोट की। ये वे संरचनात्मक विफलताएं थीं, जिन्होंने वर्षों तक एईएस और जेई के प्रसार को बढ़ावा दिया था। इसके साथ ही फ्रंटलाइन स्टाफ, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यापक क्षमता-वृद्धि ने समर्पित और सक्षम जनशक्ति तैयार की। जागरूकता अभियानों, हिंदी प्रोटोटाइप्स और जमीनी स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं एवं 'दस्तक' अभियान के माध्यम से जनजागरूकता फैलाई गई, स्वच्छता व्यवहार को नया रूप दिया गया और रोकथाम की आदतों को मजबूत किया गया। इन सब कदमों के नतीजे चौंकाने वाले रहे। एईएस के मामले 2017 में 4,759 से घटकर 2024 में 116 रह गए। जेई के मामले 677 से घटकर पांच। मौतें 2017 में एईएस से 594 और जेई से 81 थीं, जो 2024 में शून्य हो गई। सबसे अहम बात यह रही कि यह सफलता तीन कारकों से संभव हुई- केंद्र और राज्य के बीच तालमेल जिसने विभागीय और एजेंसी स्तर पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया, संरचनात्मक सुधार जिन्होंने पोषण, स्वच्छता और पानी जैसी जड़ों पर चोट की और राजनीतिक इच्छाशक्ति जिसने मिशन मोड में जवाबदेही के साथ क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी। ये सब सहकारी संघवाद का सफल उदाहरण बने, जिसने दशकों की उपेक्षा से शिकार हो रहे हजारों जीवन बचाए। उत्तर प्रदेश का यह लक्षित हस्तक्षेप राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का उत्प्रेरक बना और उसे हेल्थकेयर एवं मेडटेक का उभरता हुआ केंद्र बना दिया।

अभियान

जब वृन्दावन में रंग नहीं, भक्ति बरसती है

ब्रजभूमि की पावन धरा पर जैसे ही रंगभरी एकादशी का पावन दिवस आया, वैसे ही पूरे वृन्दावन का वातावरण भक्ति, प्रेम और रंगों की दिव्यता से भर उठा। यह कोई साधारण पर्व नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब भक्ति स्वयं रंग बनकर भक्तों के हृदय में उतरती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों के द्वार खुले और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़ीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा ब्रजधाम एक साथ जाग उठा हो और हर गली, हर चौक, हर मंदिर भगवान के प्रेम में रंग गया हो।

सबसे अधिक उत्साह और आकर्षण का केंद्र बना बांके बिहारी मंदिर, जहां रंगभरी एकादशी के साथ ही होली उत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्तों को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वे किसी दिव्य लोक में आ गए हों। मंदिर के सेवायतों ने बताया कि इस दिन भगवान बांके बिहारी स्वयं भक्तों के साथ होली खेलते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम का वह संवाद है, जिसमें रंग माध्यम बन जाता है और भक्ति उसका सार।

अनुष्ठान की शुरुआत उस पवित्र क्षण से हुई जब ठाकुर जी ने राधा रानी पर केसर, गुलाब जल और टेसू के फूलों के अर्क से भरे जल की पिचकारी चलाई। टेसू के फूलों की प्राकृतिक सुगंध ने वातावरण को और भी अधिक पवित्र बना दिया। यह सुगंध केवल हवा में ही नहीं, बल्कि हर भक्त के मन में भी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य उत्सव में भाग ले रही हो। टेसू के फूलों का यह रंग केवल शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़ता है, जो लंबे समय तक बना रहता है।

ब्रज की परंपरा के अनुसार, यह उत्सव द्वापर युग से चला आ रहा है, जब राधा रानी ने पहली बार भगवान कृष्ण के गालों पर रंग लगाया था। वही क्षण इस परंपरा की शुरुआत बना, जो आज भी उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाई जाती है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि प्रेम का वह प्रतीक है, जो समय की सीमाओं से परे है। जब भक्त इस दृश्य की कल्पना करते हैं, तो उनके मन में भी वही आनंद और प्रेम जागृत हो जाता है।

मंदिर में भगवान बांके बिहारी को इस अवसर पर सफेद वस्त्र पहनाए गए। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जो इस उत्सव की शुरुआत को दर्शाता है। यह परंपरा धुलंडी तक जारी रहती है, जब भगवान गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। सफेद से गुलाबी तक की यह यात्रा प्रेम और भक्ति की गहराई को दर्शाती है। यह परिवर्तन केवल वस्त्रों का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी होता है।

पूरे वृन्दावन में उस दिन 'आज बिरज में होली रे रसिया' जैसे पारंपरिक भजन गूंज रहे थे। इन भजनों की ध्वनि केवल कानों तक ही नहीं, बल्कि हृदय तक पहुंच रही थी। यह भजन ब्रज की आत्मा हैं, जो हर वर्ष इस उत्सव को और भी अधिक जीवंत बना देते हैं। इन भजनों की विशेषता यह है कि इन्हें केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम कवियों ने भी लिखा है, जो इस भूमि की सांस्कृतिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है।

मंदिरों में फूलों की होली भी खेली गई। भक्तों ने गुलाब और गेंदे के फूलों से भगवान को अर्पित किया और फिर उन्हीं फूलों को एक-दूसरे पर उछालकर उत्सव का आनंद लिया। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था। हवा में उड़ते फूल, गूंजते भजन, और भक्तों के चेहरे पर झलकता आनंद—यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है।

इस उत्सव में केवल स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आए भक्त भी शामिल हुए। राधा दामोदर मंदिर में 200 से अधिक विदेशी भक्तों ने इस दिव्य उत्सव में भाग लिया। उन्होंने भी भगवान के साथ होली खेली और इस परंपरा का अनुभव किया। उनके चेहरे पर जो आनंद था, वह यह दर्शाता था कि भक्ति की कोई भाषा या सीमा नहीं होती।

राधा बल्लभ मंदिर में भी विशेष आयोजन किए गए। यहां ढोल और नगाड़ों के साथ एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसने पूरे नगर को भक्ति के रंग में रंग दिया। यह शोभायात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्तों के प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन थी। ब्रज में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भगवान और भक्त के बीच प्रेम का उत्सव है। यहां रंग केवल शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़ता है। यहां होली खेलना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब भक्त भगवान के साथ होली खेलते हैं, तो वे अपने सभी दुख, चिंताएं और अहंकार भूल जाते हैं।

प्रशासन ने भी इस अवसर पर विशेष व्यवस्थाएं की थीं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं, और यह सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए थे कि केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाए, ताकि इस पवित्र उत्सव की शुद्धता बनी रहे।

यह उत्सव केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह कई दिनों तक चलता है। आने वाले दिनों में लड्डू होली, जलेबी होली और फूलों की होली जैसे विशेष आयोजन भी होंगे। हर आयोजन का अपना अलग महत्व और आकर्षण होता है। लेकिन रंगभरी एकादशी वह क्षण है, जब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है।

जब शाम हुई, तो मंदिरों में दीप जलाए गए और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। भक्तों ने भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति में डूबे हुए भजन गाए। उस समय ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो और केवल भक्ति ही शेष रह गई हो।

वृन्दावन की होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। यह वह क्षण है, जब भगवान और भक्त के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यहां रंग केवल रंग नहीं होते, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के प्रतीक होते हैं।

जब कोई वृन्दावन की होली का अनुभव करता है, तो वह केवल रंगों से नहीं, बल्कि भक्ति से भीग जाता है। और यही इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है—यह रंगों से अधिक भक्ति का उत्सव है, जो हर वर्ष लाखों लोगों के हृदय को छू जाता है और उन्हें भगवान के और भी करीब ले आता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

जल, जमीन, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य बचाने के लिए प्राकृतिक खेती ही श्रेष्ठ विकल्प : राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी

- ▶▶ राज्यपाल ने सभी विधायकों का आह्वान किया कि वे उनके क्षेत्र के एक गाँव को 'प्राकृतिक गाँव' बनाएँ
- ▶▶ मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को आज की तथा आगामी समय की जरूरत बताया
- ▶▶ 'पहेलुं सुख ते जात निरोगी' परंपरागत उक्ति के लिए प्राकृतिक खेती ही तारणोपाय है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- ▶▶ मानव जाति तथा प्रकृति की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती अपनाना अनिवार्य : विधानसभाध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी
- ▶▶ राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी की अध्यक्षता में गुजरात विधानसभा में प्राकृतिक कृषि परिसंवाद आयोजित हुआ

गांधीनगर : गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को आयोजित प्राकृतिक कृषि परिसंवाद को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने रासायनिक खेती के गंभीर परिणामों तथा प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती जैसे गंभीर विषय को आज विधानसभा में स्थान मिला है। यह आनंद की बात है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बीच का अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि जैविक खेती में एक एकड़ के लिए 300 क्विंटल गोबर खाद की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत; प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवों की खेती है। देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं और गौमूत्र खनिजों का भंडार है। जीवामृत तथा घन जीवामृत द्वारा जमीन में केंचुओं और मित्र कीटकों की संख्या बढ़ती है, जो प्राकृतिक रूप से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं।

राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की कि वर्षों पहले कैंसर, डाइबिटीज या हार्टअटैक जैसे रोगों की व्यापकता नहीं के बराबर थी, जबकि आज छोटे बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है। उन्होंने उन रिसर्च रिपोर्ट्स का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया है कि नवजात शिशु के लिए अमृत समान माता के दूध में भी अब यूरिया तथा कीटनाशक मिल रहे हैं।

भारत में हरित क्रांति के समय देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5 प्रतिशत था, जो आज घटकर 0.5 प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। राज्यपाल ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 प्रतिशत से नीचे चला जाता है, वह जमीन बंजर कहलाती है। गुजरात में रासायनिक खेती वाली जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 प्रतिशत से नीचे पहुँच चुका है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन कठोर हो जाने के कारण वर्षा जल जमीन में नहीं उतरता और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है।

राज्यपाल ने जोड़ा कि प्राकृतिक खेती में केंचुए जमीन में प्राकृतिक रूप से छिद्र बनाते हैं, जिसके चलते जमीन में वर्षा जल संग्रह होता है।

राज्यपाल ने कहा कि यूरिया-डीएपी की सब्सिडी पर देश के करोड़ों रुपए बरबाद किए जाते हैं। यदि प्राकृतिक खेती अपनाई जाए, तो यह खर्च बच सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में समग्र देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन लागू हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों से गुजरात में हाल में 8 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक कृषि अपनाई है।

राज्यपाल ने कहा कि यह जरूरी है कि किसान शुरुआत में अपने खेत के एक भाग में प्राकृतिक खेती करें। इसके अलावा; राज्यपाल ने विधानसभा के सभी सदस्यों का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र के एक गाँव को 'प्राकृतिक गाँव' अवश्य बनाएँ।

राज्यपाल ने जल, जमीन, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को अनिवार्य बताते हुए कहा कि गुजरात सरकार के सहयोग से यह मिशन अब जन आंदोलन बन चुका है। यदि हमें आने वाली पीढ़ी को कैंसर जैसे घातक रोगों से बचाना है और किसानों की आय दुगुनी करनी है, तो प्राकृतिक खेती के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्राकृतिक खेती को आज के और आने वाले समय; दोनों की अनिवार्यता बताते हुए कहा कि 'पहेलुं सुख ते जात निरोगी (पहला सुख निरोगी काया)'; इस परंपरागत उक्ति के लिए प्राकृतिक खेती तारणोपाय है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'बैक टु बेसिक' मंत्र की भूमिका देते हुए जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने इस मंत्र द्वारा केवल प्राकृतिक खेती के ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी स्रोतों के संवर्धन का मार्ग भी बताया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा पानी की समस्या के निवारण के लिए कैच दे रेन, ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौतियों से निपटने एवं ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और स्वस्थता के लिए रसायनमुक्त खेती के दिए गए अभियानों को व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी की प्रेरणा एवं सघन मार्गदर्शन से प्राकृतिक खेती के जन आंदोलन बनने पर हर्ष व्यक्त किया। श्री पटेल ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के इस कार्य को भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखने का आत्मसंतोषपूर्ण कार्य बताया और विश्वास व्यक्त किया कि प्राकृतिक खेती का यह परिसंवाद अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।

इससे पहले गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि जीवन जीने के लिए अत्यावश्यक हवा एवं पानी को शुद्ध रखने के लिए 'प्राकृतिक कृषि' को अधिक से अधिक प्राथमिकता देना आवश्यक है और राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी गुजरात की जनता के लिए निरंतर संवेदनशीलतापूर्वक यह कार्य कर रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि गुजरात ने पूज्य महात्मा गांधी तथा सरदार साहब के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया है, जबकि आज सुशासन से देश एवं विश्व को दिशा देने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कर रहे हैं।

विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल स्वयं गाँव-गाँव किसानों के बीच जाकर प्राकृतिक कृषि के फायदे बता रहे हैं। उन्होंने जोड़ा कि इस वर्ष गुजरात सरकार ने प्राकृतिक कृषि संबंधी बजट में भी बहुत बड़ी घोषणा की है। हमें प्रयास करना होगा कि यह कार्य केवल सरकार का न रहे, बल्कि विधानसभा के माध्यम से भी गुजरात के सुदूरवर्ती नागरिक तक पहुँचे।

अंत में आभार व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि गुजरात विधानसभा में इस प्रकार के प्राकृतिक कृषि संबंधी परिसंवाद का आयोजन होना समग्र गुजरात के लिए गौरव की बात है। प्राकृतिक कृषि के ऋषि और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने इस परिसंवाद के माध्यम से सभी को बहुत सरल भाषा में प्राकृतिक कृषि संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया है।

श्री वाघाणी ने सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि आज के समय में मानव जीवन के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अतः सभी जन प्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र में निजी रुचि लेकर प्राकृतिक कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस अवसर पर संसदीय मामलों के मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री पूर्णेशभाई मोदी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, सांसद, विधायक, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक, साहित्यकार, मीडिया क्षेत्र के संपादक व प्रतिनिधि तथा प्राकृतिक खेती करने वाले किसान उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा 1 मार्च 2026 को चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल के बीच जम्बो ब्लॉक

(जीएनएस)। आवश्यक अनुरक्षण कार्य हेतु अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर पाँच घंटे का ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा रविवार, 1 मार्च 2026 को ट्रैक, सिगनलिंग प्रणाली तथा ओवरहेड उपकरणों के अनुरक्षण हेतु चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 10:35 बजे से 15:35 बजे तक कुल पाँच घंटे का होगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान स्लो लाइन की सभी ट्रेनें चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच फास्ट लाइनों पर चलाई जाएँगी। इसके अलावा, कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय सेवाएँ निरस्त रहेंगी, जबकि चर्चगेट की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को बांद्रा/दादर पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट कर वहीं से रिटर्न चलाया जाएगा। प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएँ।

साबरमती-दानापुर के मध्य होली स्पेशल ट्रेन का संचालन

(जीएनएस)। आगामी होली पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती एवं दानापुर के मध्य विशेष किराये पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09427/09428 साबरमती–दानापुर–साबरमती स्पेशल (विशेष किराये पर) (02 ट्रिप)

ट्रेन संख्या 09427 (साबरमती–दानापुर स्पेशल)

दिनांक 01 मार्च, 2026 (रविवार) को साबरमती से प्रातः 08.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन (सोमवार) 17.30 बजे दानापुर पहुँचेगी।

ट्रेन संख्या 09428 (दानापुर–साबरमती स्पेशल)

दिनांक 02 मार्च, 2026 (सोमवार) को दानापुर से रात्रि 22.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन (बुधवार) प्रातः 06.45 बजे साबरमती पहुँचेगी।

मार्ग एवं ठहराव

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

आरक्षण

ट्रेन संख्या 09427 की बुकिंग तत्काल प्रभाव से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की अधिकृत वेबसाइट पर प्रारंभ कर दी गई है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

सूरत नगर निगम में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अवैध निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम, जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, के अधिकारी या पदाधिकारी अपनी मनमानी नीतियों के बल पर शासन करते हुए भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे देते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि 15 लाख रुपये की लंबी रिश्वत मांगने के बाद विपुल गणेशवाला जैसे पत्रकार को 4 लाख रुपये लेकर भागने का मौका मिल जाता है। यहां हमें कार्यकारी अभियंता विपुल गणेशवाला की बात करनी होगी, जो हाल ही में रिश्वतखोरी के जाल में फंसकर बच निकले, और उनके बिचौलिए गणेशवाला की, जो पत्रकार लाइसेंस लेकर लिंबायत जोन में काम कर रहे थे। गणेशवाला के कार्यकाल के दौरान लिंबायत जोन में कई बाजार निर्माण अवैध रूप से किए गए। लिंबायत जोन में ही 100 से अधिक बाजार निर्माण एसएमसी की नीतियों और नियमों का उल्लंघन करते हुए और योजना के विरुद्ध बनाए गए हैं। निलंबित कार्यकारी अभियंता गणेशवाला ने 3-4 मंजिला मकानों के निर्माण के संबंध में नोटिस भी जारी किए और उन्हें निर्माण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लिंबायत जोन में अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को गिराते समय सूरत नगर निगम के अधिकारियों के हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन दुकानों की सड़कों पर कपड़े की बोरियां बिछाकर बनाए गए दबाव के कारण छोटी से छोटी गाड़ियों को भी चलने में दिक्कत हो रही है। कार्यकारी अभियंता विपुल गणेशवाला को ऐसी अवैध रूप से बनी इमारतों को गिराने से कौन रोक रहा था? साथ ही, अगर निर्माण स्वीकृत योजना और नियमों के विरुद्ध किया गया था, तो शहर के हित में ऐसी अवैध इमारतों को गिराने से गणेशवाला को कौन रोक रहा था? सिर्फ नोटिस देने से अवैध इमारतों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों पहले जब अवैध इमारतें बनी थीं, तब भी गणेशवाला जैसा कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा? गणेशवाला ने लिंबायत जोन के निर्माण क्षेत्र में हलचल मचा दी थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। गणेशवाला ने अपने चार साल के कार्यकाल में कोई भी निर्माण नहीं छोड़ा, चाहे वह स्वीकृत योजना के अनुसार हो या उसके विरुद्ध। बड़ा सवाल यह है कि इस क्षेत्र के पार्षद भी इससे नाराज क्यों हो गए?

शून्य त्रुटि विज्ञापन,अगर सूरत नगर निगम

सफाई कर्मचारियों से लेकर आम कर्मचारियों तक, अन्य कर्मचारियों को अतीत और वर्तमान में एक सामान्य छुट्टी जैसे अपराध के लिए घर का दरवाजा दिखा रहा है , तो विपुल गणेशवाला को घर का दरवाजा दिखाने में सूरत नगर निगम क्यों हिचकिचा रहा है? विपुल गणेशवाला एक भ्रष्ट और मनमानी करने वाला कार्यकारी अभियंता है और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उसकी संपत्ति उसकी आय से अधिक है, फिर भी उसे आज तक कानूनी रूप से नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? यह सवाल चर्चा के दलदल में खोता जा रहा है।

सोना वायदा में 502 रुपये और चांदी वायदा में 6581 रुपये की वृद्धिः क्रूड ऑयल वायदा में 4 रुपये का सुधार

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 18493.07 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 280862.55 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 13869.14 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39935 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 299355.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 18493.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 280862.55 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39935 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1582.03 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13869.14 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 160050 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160719 रुपये और नीचे में 159816 रुपये पर पहुंचकर, 159709 रुपये के पिछले बंद के सामने 502 रुपये या 0.31 फीसदी की तेजी के संग 160211 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1572 रुपये या 1.23 फीसदी की तेजी के संग 129225 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 3 रुपये या 0.02 फीसदी गिरकर 16236 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 158249 रुपये के भाव पर खूलकर, 158500 रुपये के दिन के उच्च और 157650 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 448 रुपये या 0.28 फीसदी की तेजी के संग 158036 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 159239 रुपये के भाव पर खूलकर, 159500 रुपये के दिन के उच्च और 158790 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158633 रुपये के पिछले बंद के सामने 366 रुपये या 0.23 फीसदी की तेजी के संग 158999 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 267500 रुपये के भाव पर खूलकर, 268301 रुपये के दिन के उच्च और 264100 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 259669 रुपये के पिछले बंद के सामने 6581 रुपये या 2.53 फीसदी की बढ़त के साथ 266250 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6244 रुपये या 2.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 271500 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 5886 रुपये या 2.23 फीसदी की तेजी के संग 270045 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 2856.40 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 13.5 रुपये या 1.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1215.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 9.95 रुपये या 3.06 फीसदी की बढ़त के साथ 335 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 2.4 रुपये या 0.78 फीसदी की मजबूती के साथ 310.95 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 45 पैसे या 0.24 फीसदी चढ़कर 189.9 रुपये प्रति किलो हुआ। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1494.96 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 5950 रुपये के भाव पर खूलकर, 6071 रुपये के दिन के उच्च और 5942 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 4 रुपये या 0.07 फीसदी की तेजी के संग 6057 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 7 रुपये या 0.12 फीसदी की तेजी के संग 6060 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 258.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 261.2 रुपये और नीचे में 257.5 रुपये पर पहुंचकर, 257.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.2 रुपये या 1.24 फीसदी बढ़कर 260.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 3.3 रुपये या 1.28 फीसदी की तेजी के संग 260.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 948 रुपये पर खूलकर, 3.5 रुपये या 0.37 फीसदी गिरकर 942 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7048.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6820.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2436.54 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 188.12 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 5.89 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 220.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 749.51 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 733.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.95 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9422 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74557 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28097 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 354580 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 50378 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9713 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 16595 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 56785 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17103 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 28004 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 39935 पॉइंट पर खूलकर, 39935 के उच्च और 39935 के नीचले स्तर को छूकर, 446 पॉइंट बढ़कर 39935 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 9.6 रुपये की बढ़त के साथ 383 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2 रुपये की बढ़त के साथ 17.1 रुपये हुआ। सोना फरवरी 163000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 93 रुपये की गिरावट के साथ 67 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 282.5 रुपये की बढ़त के साथ 12948 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.4 रुपये की बढ़त के साथ 14 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.02 रुपये की बढ़त के साथ 7.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 9.2 रुपये की गिरावट के साथ 312.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.3 रुपये की गिरावट के साथ 16.9 रुपये हुआ। सोना फरवरी 158000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 387.5 रुपये की गिरावट के साथ 89.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 375 रुपये की गिरावट के साथ 1688.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.72 रुपये की गिरावट के साथ 26.25 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 89 पैसे के सुधार के साथ 5.7 रुपये हुआ।

मलाड में फलों पर जहर छिड़कते विक्रेताओं को पकड़े जाने से जनता में भारी आक्रोश और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हुईं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। मुंबई के मलाड में फल विक्रेताओं द्वारा फलों पर चूहे मारने की दवा छिड़कने का एक चौंकाने वाला वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके आधार पर मलाड पुलिस ने मनोज केसरवानी और बिपिन केसरवानी नाम के दो फल विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कई सालों से स्थानीय बाजार में फल बेचते आ रहे हैं। फिर, पूरा मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय निवासी ने आरोपियों द्वारा फलों पर रैटोल नामक जहर छिड़कते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चूहों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए रात में सेब और अनार जैसे फलों पर रैटोल छिड़कते थे। रैटोल में मौजूद पीला फास्फोरस मानव शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है।

शून्य त्रुटि एजेंसी

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वे रात में चूहों से फलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फलों पर रैटोल नामक चूहे मारने की दवा लगाते थे। पिछले मंगलवार की रात, कुछ सतर्क नागरिकों ने आरोपियों को फलों पर पीले रंग का क्रीम जैसा पदार्थ लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो आरोपियों ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। खुले बाजार में बिकने वाले फलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, रैटोल में पीले फास्फोरस जैसे अत्यधिक विषैले रसायन होते हैं, जो मानव शरीर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। यह विष रक्त में प्रवेश कर सकता है और शरीर में पहुँचते ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष चिंता की बात यह है कि यदि ऐसा विषैला पदार्थ फल की त्वचा में समा जाए, तो केवल पानी से धोने से इसका प्रभाव पूरी तरह से दूर नहीं होता। छोटे बच्चे अक्सर फलों को ठीक से धोए या छीले बिना ही खा लेते हैं। इससे जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि फलों को कम से कम 20 मिनट के लिए नमक मिले गुनगुने पानी में भिगोकर रखें और यदि संभव हो तो छीलकर ही खाएं।

सेमीकंडक्टर की चिप बनाने के लिए अत्यंत स्वच्छ रूम जरूरी, साणंद में माइक्रोन का क्लीनरूम विश्व के सबसे बड़े क्लीनरूम की सूची में शामिल

- ▶▶ साणंद प्लांट के प्रथम फेज में निर्मित क्लीनरूम का क्षेत्र 5 लाख वर्ग फीट, एफिल टावर से साढ़े तीन गुना अधिक स्टील का उपयोग : संजय मेहरोत्रा, अध्यक्ष एवं सीईओ, माइक्रोन टेक्नोलॉजी
- ▶▶ ऑपरेशन थियेटर से भी अधिक स्वच्छ होता है क्लीनरूम, एक छोटे कण या तापमान में 1 डिग्री के परिवर्तन से भी मशीन का कार्य ठप हो सकता है

(जीएनएस)। गांधीनगर : सेमीकंडक्टर चिप की उत्पादन प्रक्रिया में क्लीनरूम महत्वपूर्ण होता है। चिप के उत्पादन में वातावरण का पूर्णतः स्वच्छ होना जरूरी है, कारण कि हवा में मौजूद अत्यंत छोटे कण भी चिप में घुसकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों तथा सेमीकंडक्टर के उत्पादों के लिए क्लीनरूम बनाया जाता है। साणंद में माइक्रोन कंपनी द्वारा बनाया गया क्लीनरूम विश्व के सबसे बड़े क्लीनरूम की सूची में शामिल हो गया है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष एवं सीईओ संजय मेहरोत्रा के अनुसार माइक्रोन के साणंद प्लांट में प्रथम फेज में 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में क्लीनरूम का निर्माण किया गया है, जिसमें एफिल टावर से साढ़े तीन गुना अधिक लोहे तथा ओलंपिक आकार के 100 स्विमिंग पूल जितने कंक्रीट का उपयोग किया गया है।

मोदी सरकार ने मजबूत सहयोग दिया, निवेश के लिए प्रोत्साहित किया : संजय मेहरोत्रा

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमें मजबूत सहयोग दिया है और कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनाई हैं। साणंद का प्रोजेक्ट भारत में एक अग्रणी प्रोजेक्ट है तथा केन्द्र व गुजरात सरकार के साथ भागीदारी में कार्य करने का हमें गर्व है।

क्लीनरूम की हवा कई बार ऑपरेशन थियेटर से भी अधिक स्वच्छ

माइक्रोन टीम द्वारा बताया गया कि साणंद के माइक्रोन प्लांट में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विशाल क्लीनरूम बनाया गया है। इस क्लीनरूम में मौजूद हवा कई बार ऑपरेशन थियेटर से भी अधिक स्वच्छ होती है। यहाँ एक बाल भी चिप को नुकसान पहुँचा सकता है। इस कारण उसे अत्यंत स्वच्छ रखना जरूरी है।

क्लीनरूम को स्वच्छ रखने के लिए फिल्टर्ड हवा को ऊपर से नीचे (वर्टिकली) समान मात्रा में भेजा जाता है। यह हवा अस्त-व्यस्त नहीं होती है और एक समान लय में प्रवाहित होती है। क्लीनरूम का नीचे वाला फ्लोर भी जमीन की सतह से थोड़ा ऊँचाई पर बनाया हुआ होता है, जिसके नीचे हवा गुजरती है और कूलिंग, पावर तथा डेटा का कार्य चलता रहता है। क्लीनरूम में तापमान में लगभग एक डिग्री का फर्क पड़े, तो भी मशीन के कार्य में वह विक्षेप पहुँचा सकता है। इसलिए तापमान को निरंतर अत्यंत सूक्ष्म स्तर तक नियंत्रित किया जाता है, कारण कि मेमोरी टेस्टर मशीनों से तापमान में बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है। एक सूक्ष्म कण भी अगर चिप में प्रवेश कर जाए, तो वर्षों बाद भी वह प्रोडक्ट में नुकसान पैदा कर सकता है। यहाँ पावर, कूलिंग तथा हवा के लिए पर्याप्त बैकअप प्रणाली रखी गई है, जिससे किसी एक सिस्टम में कोई विक्षेप हो, तो कामकाज पूर्ववत रखा जा सके। माइक्रोन के वैश्विक गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार इस क्लीनरूम को भारत में डिजाइन किया गया है। इस प्लांट के शुभारंभ से भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत दावेदारी दर्ज कराएगा। कंपनी 2019 से भारत में कार्यरत है। बेंगलुरु तथा हैदराबाद में कंपनी के रिसर्च एवं डेवलपमेंट केन्द्र सक्रिय हैं। हाल में माइक्रोन भारत में लगभग 24,000 लोगों को रोजगार देता है। भारत में कार्यरत कर्मचारी कंपनी के वैश्विक इनोवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी के कुछ सर्वाधिक अत्याधुनिक डीआरएएम मेमोरी उत्पाद अमेरिका की टीमों के सहयोग से भारत में डिजाइन किए गए हैं।

गुजरात के शहरीजनों को मनोरंजक गतिविधियों के लिए वाइब्रेंट कम्युनिटी स्पेस प्रदान करने के लिए राज्य की महानगर पालिकाओं में विकसित होंगे थीम-आधारित 'नमो गौरव पार्क'

- ▸▸ राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में नमो गौरव पार्क के लिए शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के तहत 20 करोड़ रुपए आवंटित किए
- ▸▸ 100 करोड़ रुपए के प्रस्तावित खर्च से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी आयु वर्ग के लोगों को आधुनिक और आकर्षक मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी
- ▸▸ पार्क में सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक समारोहों और नियोजित कार्यक्रमों के आयोजन से शहरी समुदायों के बीच संबंध मजबूत होगा
- ▸▸ पौधरोपण, थीमैटिक ग्रीन लैंडस्केप्स और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं से अर्बन इकोलॉजी में होगा सुधार

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के शहरी क्षेत्रों में अब विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन स्थलों की मांग बढ़ रही है। ऐसे वाइब्रेंट कम्युनिटी स्पेस, जो मनोरंजन के साथ-साथ समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली को भी बढ़ावा देते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए खुले स्थान कम होते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने राज्य की महानगर पालिकाओं में थीम-आधारित 'नमो गौरव पार्क' विकसित करने का निर्णय किया है। ऐसे थीम-आधारित पार्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उल्लेखनीय है कि थीम-आधारित पार्क कई प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें खेल, फिटनेस और सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्यावरणीय (इकोलॉजी) और टेक्नोलॉजी-आधारित सुविधाएं शामिल हैं। ऐसे पार्क न केवल शहरी क्षेत्रों में रहने के माहौल को ज्यादा बेहतर बनाते हैं, बल्कि ग्रीन कवर को बढ़ाकर, जैव विविधता को प्रोत्साहन देकर और सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों में सुधार करके जलवायु संरक्षण में भी सहयोग करते हैं।

नमो गौरव पार्क विकसित करने के उद्देश्य

थीम-आधारित नमो गौरव पार्क विकसित करने का उद्देश्य शहरीजनों की मनोरंजन और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने वाले सुरक्षित, समावेशी और वाइब्रेंट कम्युनिटी स्थलों का निर्माण करना है। इस पहल के माध्यम से बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को आधुनिक एवं आकर्षक मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, इस पार्क में विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों के जोन बनाए जाएंगे, जो शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक सेहत और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देंगे। पार्क में सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक समारोहों और नियोजित कार्यक्रमों के आयोजन से शहरी समुदायों के बीच संबंध मजबूत होगा। इसके अलावा, इस पार्क को विकसित करने का एक उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण को प्रोत्साहन देना भी है। विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों को लगाने, थीमैटिक ग्रीन लैंडस्केप्स और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं से अर्बन इकोलॉजी बेहतर होगी। यही नहीं, ग्रीन कवर में वृद्धि, जल संरक्षण को टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करके क्लाइमेट रेजिलिएंस यानी जलवायु के प्रति लचीलेपन में भी सुधार किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से शहरी जीवन की समग्र गुणवत्ता बेहतर होगी।

नमो गौरव पार्क में शामिल विभिन्न कंपोनेंट्स

नमो गौरव पार्क में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें चिल्ड्रन प्ले जोन, थीम-आधारित लैंडस्केपिंग एंड ग्रीन जोन, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एरिया, मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधि स्थल, जल निकाय और इको फ्रेंडली फीचर्स, सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वभौमिक सुगम्यता तथा स्मार्ट पार्क फीचर्स शामिल हैं। चिल्ड्रन प्ले एरिया में बच्चों के लिए खेल के सामान होंगे, तो थीम-आधारित लैंडस्केपिंग एंड ग्रीन जोन में स्थानीय पेड़-पौधे और फूलों की क्यारियां तथा थीम-आधारित शिल्प एवं कलाकृतियां लगाई जाएंगी, साथ ही बटरफ्लाई गार्डन और हर्बल गार्डन आदि भी होंगे। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एरिया में ओपन जिम, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक तथा बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे खेलों के स्थान होंगे। मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधि स्थल में ओपन एयर एम्फीथिएटर या प्रदर्शन के लिए स्टेज, योग और ध्यान के लिए लॉन बनाए जाएंगे। जल निकाय और पर्यावरण-अनुकूल फीचर्स में छोटे तालाब, फव्वारे, हरित क्षेत्रों के लिए टपक सिंचाई और वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि विकसित किए जाएंगे। सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वभौमिक सुगम्यता के अंतर्गत पेयजल की सुविधा, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय, बैठने के लिए बेंच और गजेबो तथा दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक रास्ते बनाए जाएंगे। वहीं, स्मार्ट पार्क फीचर्स में सौर ऊर्जा से संचालित गार्डन, वाई-फाई की सुविधा, सेंसर-आधारित लाइटिंग सिस्टम और डिजिटल इन्फॉर्मेशन साइनेज आदि शामिल किए जाएंगे। ऐसे थीम-आधारित नमो गौरव पार्क का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किए गए रणनीतिक शहरी निवेश को दर्शाता है, जो शहरी जीवन के पर्यावरणीय, मनोरंजक और सामाजिक-सांस्कृतिक परिमाणों को मजबूत करते हैं। यह पहल राज्य के समावेशी, जनोन्मुखी और जलवायु-लचीले शहरी विकास के विजन का समर्थन देती है, साथ ही महानगर पालिका क्षेत्रों में 'ईज ऑफ लिविंग' में भी सुधार करती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य भारत को 'सेमीकंडक्टर हब' बनाना : श्री अर्जुन मोढवाडिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

- ▸▸ महात्मा मंदिर में 1 मार्च को आयोजित होगी 'गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026' : श्री अर्जुन मोढवाडिया
- ▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की विशेष उपस्थिति

(जीएनएस)। गांधीनगर : जब दुनिया कोविड-19 की चुनौतियों से जूझ रही थी, तब कुछ सेक्टरों की सप्लाई चेन विशेष रूप से प्रभावित हो गई थी, जिनमें सेमीकंडक्टर सेक्टर महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन बंद होने से दुनिया के कई उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। यह एक बड़ी चुनौती थी, इस चुनौती को एक अवसर मानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का निर्णय किया, जिसके परिणामस्वरूप आज देश सेमीकंडक्टर सहित 5वीं पीढ़ी की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इस संबंध में गत सप्ताह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 आयोजित हुई, जिसमें दुनिया के लगभग 88 देशों ने साथ मिलकर एआई के एथिकल (नैतिक) उपयोग के लिए घोषणापत्र जारी किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढडिया ने शुक्रवार को गांधीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात भी सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में देश का हब बनने जा रहा है। राज्य में 1.24 लाख करोड़ रुपए अनुमानित लागत की सेमीकंडक्टर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। श्री मोढवाडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात भारत के अग्रणी सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और रणनीतिक टेक्नोलॉजी आधार को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत, आगामी 1 और 2 मार्च को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026' का आयोजन होगा। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि गुजरात को मेमोरी पैकेजिंग और उन्नत सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। गुजरात सेमीकनेक्ट 2026 का आयोजन राज्य के फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक और स्वदेशी सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स भागीदारों को एक मंच पर इकट्ठा करना है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हाई-टेक चिप विनिर्माताओं, सप्लाई चेन भागीदारों और स्थानीय उद्योगों के बीच रणनीतिक सहयोग को सक्षम बनाकर गुजरात में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के दीर्घकालिक विकास को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि इस वैश्विक कॉन्फ्रेंस का तीसरा संस्करण सेमीकनेक्ट 2024 और 2025 की मजबूत गति पर आधारित है, जिसने सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के प्रमुख हितधारकों- फैब्स, फाउंड्रीज, मुख्य उपकरण और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं एवं अग्रणी डिजाइन इकोसिस्टम भागीदारों को सफलतापूर्वक एक मंच पर इकट्ठा किया था। पहले के संस्करणों ने एकीकृत बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) और बी2जी (बिजनेस-टू-गवर्नमेंट) बैठकों, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी और विषय-आधारित सत्रों के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन, सप्लाई चेन विकास, नवाचार और प्रतिभा निर्माण में सार्थक साझेदारियों को सक्षम बनाया था। इस कॉन्फ्रेंस के लिए अब तक 8 से अधिक देशों से उद्योग प्रतिनिधियों, विदेशी संस्थानों, अनुसंधानकर्ताओं, नवोन्मेषकों, निवेशकों और विद्यार्थियों सहित 2500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य निवेशकों की उपस्थिति भी रहेगी, जिनमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के डॉ. रणधीर ठाकुर, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के श्री संजय मेहरोत्रा, सीजी सेमी के श्री जी.सी. चतुर्वेदी, केन्स सेमीकॉन के श्री रमेश कुन्हीकन्नन और वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग, उपकरण निर्माताओं एवं सप्लाई चेन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मैटेरियल्स इंटरनेशनल (सेमी) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री अजित मनोचा शामिल हैं।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नए निवेशों और कौशल विकास पहलों से जुड़ी घोषणाएं करने की योजना है।

कॉन्फ्रेंस में वैश्विक और भारतीय अग्रणी विशेषज्ञों के साथ केंद्रित पैनल सत्र आयोजित होंगे, जिनमें निम्न सत्र शामिल हैः-

पैनल 1 – 'नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर्स'- रघु पणिकर (सीईओ, कन्स सेमीकॉन), हेम टेकर (वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट), माइक्रोन टेक्नोलॉजी) और वेंकट सिम्हाद्री (संस्थापक और प्रबंध निदेशक, एएसआईपी टेक्नोलॉजीज) जैसे मुख्य वक्ता इस बात पर चर्चा करेंगे कि गुजरात लीगेसी नोड्स से उन्नत सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विनिर्माण में किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है। वे कटिंग-एज टेक्नोलॉजी निवेश आकर्षित करने, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करने और डिजाइन, फैब्रिकेशन एवं सप्लाई चेन कार्यक्षमता में नवाचार के जरिए वैश्विक वैल्यू चेन में एकीकरण की भारत की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

पैनल 2 – 'लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर'- विनायक पाई (सीईओ, टाटा प्रोजेक्ट्स) और ताकायोशी यूचियमी (क्षेत्रीय उप प्रमुख, निप्पॉन एक्सप्रेस) जैसे प्रतिष्ठित वक्ता धोलेरा एवं साणंद जैसे हब में सेमीकंडक्टर उत्पादन को समर्थन देने के लिए विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सुरक्षित सप्लाई चेन को सक्षम बनाने पर चर्चा करेंगे। यह पैनल बंदरगाहों की तैयारी, विशिष्ट परिवहन, ऊर्जा ढांचा और पाइपलाइन-आधारित लॉजिस्टिक्स जैसे उच्च-सूक्ष्म सेमीकंडक्टर कार्यों के लिए आवश्यक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

पैनल 3 – 'सेमीकंडक्टर फाइनेंसिंग'- दीपेश शाह (कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए), अविचल खेड़ा (सीएफओ, गिफ्ट सिटी) और वी. बाला (सीईओ, एनएसई आईएक्स) जैसे प्रतिष्ठित महानुभाव बताएंगे कि कैसे गिफ्ट - आईएफएससी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी – इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर) भारत की सेमीकंडक्टर आशाओं के लिए वित्तीय शक्ति का केंद्र बन सकता है। विशेषज्ञ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वैश्विक पूंजी प्रवाह, नई वित्तीय व्यवस्थाएं, निवेश-अनुकूल विनियमन और आईएफएससी आधारित संस्थान बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर फैब्स और इकोसिस्टम विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

पैनल 4 – 'अनुसंधान और वर्कफोर्स'- एस.डी. सुदर्शन (ईडी, सीडीएसी), डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी (डीजी, एनआईईएलआईटी) और डॉ. रजत मूना (डीजी, आईआईटी-गांधीनगर) जैसे प्रतिष्ठित वक्ता सेमीकंडक्टर अनुसंधान, उन्नत कौशल विकास और मानव संसाधान निर्माण में भारत के क्षमतावर्धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पैनल आरएंडडी संस्थानों, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग और विशिष्ट कुशलता मार्गों के महत्व को उजागर करेगा।

पैनल 5 – 'इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम'- अनुराग धूत (एमडी, एपिटोम), स्नेह शाह (निदेशक, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स) और विलियम ड्यू (सीएमओ, पोलराइस) जैसे मुख्य वक्ता पीसीबी उत्पादन से लेकर मजबूत घटक सप्लाई चेन तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को सक्षम बनाने पर प्रकाश डालेंगे।

कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय और उद्योग संबंधों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उच्च स्तरीय बैठकें भी आयोजित होंगी :

ताइवान कंट्री राउंडटेबल : भारत की पहली व्यापारी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा और व्यापक इकोसिस्टम सहयोग के लिए टेक्नोलॉजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित।

जापान कंट्री राउंडटेबल : गुजरात में क्षमतावर्धन के लिए जापान के सुस्थापित अपस्ट्रीम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ संवाद।

माइक्रोन इकोसिस्टम राउंडटेबल : स्थानीय वैल्यू चेन के निर्माण के लिए माइक्रोन के वैश्विक सप्लायर्स की भागीदारी।

वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड फ्यूचर स्किल्स 'फ्रॉम सिलिकॉन टू स्टूडेंट्स' सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में करियर मार्ग और कौशल विकास पर मार्गदर्शन।

इसके अलावा, वरिष्ठ उद्योग लीडरों एवं सरकारी अधिकारियों के बीच चुनिंदा वन-टू-वन बैठकें भी आयोजित होंगी।

इसके अतिरिक्त, 2 मार्च को प्रतिनिधिगण धोलेरा सेमीकॉन सिटी का दौरा करेंगे, जहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और वरिष्ठ अधिकारी साथ बैठक करेंगे। आगंतुक धोलेरा के प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक ढांचे, बिजली और पानी के सिस्टम, लॉजिस्टिक्स तैयारियों और सेमीकंडक्टर से संबंधित चल रहे विकास का सीधा अनुभव करेंगे।

कॉन्फ्रेंस को वैश्विक और राष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों का मजबूत समर्थन मिला है, जिनमें सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मैटेरियल्स इंटरनेशनल (सेमी), जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो-जापान), कोरिया व्यापार-निवेश संवर्धन एजेंसी (कोटरा-कोरिया), इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम), इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएलसीआईएनए), इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए), मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एमईडीईपीसी) और इन्वेस्ट इंडिया शामिल हैं।

इस कॉन्फ्रेंस में यू योशिदा सेन (डीजी, जेट्रो, अहमदाबाद), श्री किम (निदेशक, कोटरा, अहमदाबाद) और श्री होमर चांग (डीजी, टीईसीसी, मुंबई) भी मौजूद रहेंगे। गुजरात सेमीकनेक्ट 2026 राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

भावनगर रेलवे मंडल में पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मैजिक एवं पपेट शो का सफल आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की अपनी सतत पहल के अंतर्गत दिनांक 26 फरवरी, 2026 (गुरुवार) को भावनगर रेलवे कम्युनिटी हॉल में बच्चों एवं परिवारजनों हेतु मनोरंजक एवं रचनात्मक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पपेट शो एवं मैजिक शो ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति, रचनात्मकता तथा आकर्षक शैली से उपस्थित बच्चों एवं

दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दोनों प्रस्तुतियों को दर्शकों की ओर से अत्यंत सराहना प्राप्त हुई तथा पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहा। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने पपेट शो के कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें 2100/- का नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इसी क्रम में प्रभावशाली एवं मनोरंजक मैजिक शो के कलाकारों को उनकी शानदार प्रस्तुति हेतु 4000/- का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा संचालित किड्स हट्स एवं बाल मंदिर स्कूल के बच्चे, शिक्षकगण तथा महिला कल्याण संगठन की सदस्याओं की सक्रिय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा आयोजन को अत्यंत सफल, प्रेरणादायक एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयोगी बताया।

भावनगर मंडल द्वारा इस प्रकार के आयोजन बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ रेलवे परिवार के बीच आपसी समन्वय एवं सकारात्मक पारिवारिक वातावरण को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

करोड़ों की ठगी कर पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी आखिरकार पुणे से गिरफ्तार, निवेशकों ने ली राहत की सांस

(जीएनएस)। राजकोट। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के सनसनीखेज मामले में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी प्रदीप खोड़ाभाई डावेरा आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद न केवल पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली है, बल्कि उन सैकड़ों निवेशकों के मन में भी न्याय की उम्मीद फिर से जाग उठी है, जो पिछले कई वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 36 वर्षीय प्रदीप खोड़ाभाई डावेरा के खिलाफ पहले से ही गंभीर आर्थिक अपराधों के कई मामले दर्ज थे। वह मूल रूप से राजकोट जिले के भरुडी क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से लोगों को निवेश के नाम पर ठगने का धंधा चला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ जामनगर, राजकोट और आसपास के क्षेत्रों में गुजरात प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (GPID) एक्ट, प्राइज और चीट मनी एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल पांच गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा चेक बाउंस से संबंधित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसके खिलाफ 112 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिनमें जूनागढ़, गोंडल, वांकानेर और ओखा जैसे शहर शामिल हैं। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली घटना 7 फरवरी को सामने आई थी, जब आरोपी को एक चेक रिटर्न मामले में सुनवाई के लिए गोंडल कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत में पेशी के बाद जब पुलिस टीम उसे वापस लेकर लौट रही थी, तब रास्ते में भरुडी टोल प्लाजा के पास एक होटल में कुछ देर के लिए रुकी। इसी दौरान आरोपी के भाई संदीप ने बिना नंबर प्लेट वाली कार से वहां पहुंचकर पुलिस को चकमा देते हुए प्रदीप को फरार करा दिया। यह घटना पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने वाली थी और इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था।

आरोपी के फरार होने के तुरंत बाद गोंडल तालुका पुलिस ने उसके खिलाफ फरारी का मामला दर्ज किया और उसकी तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। राजकोट रूरल लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी और मानव खुफिया तंत्र का सहारा लिया। पुलिस निरीक्षक वी.वी. ओडेडारा और उप निरीक्षक एच.सी. गोहिल के नेतृत्व में टीम ने लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की।

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे शहर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत पुणे रवाना हुई और वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में वापस राजकोट लाया गया और गोंडल तालुका पुलिस को सौंप दिया गया, जहां उससे आगे की पूछताछ की जा रही है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदीप डावेरा ने वर्ष 2017 में "आशीष क्रेडिट सोसाइटी" और "समय ट्रेडिंग" नाम से संस्थाएं शुरू की थीं। इन संस्थाओं के माध्यम से उसने लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा देने का लालच दिया और बड़ी संख्या में लोगों से निवेश करवाया। शुरुआत में कुछ निवेशकों को रिटर्न देकर उसने विश्वास कायम किया, लेकिन बाद में करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गया। उसके झांसे में आने वालों में बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत इन योजनाओं में लगा दी थी।

बताया जाता है कि आरोपी पहले राजकोट के ग्रीनलैंड चौकड़ी के पास मणिनगर क्षेत्र में रहता था, लेकिन जब उसके खिलाफ शिकायतें बढ़ने लगीं तो उसने अपना ठिकाना बदल लिया और बाद में सूरत के पाल गांव में रहने लगा। वहां से भी वह लगातार लोगों को ठगने का काम करता रहा और पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपना स्थान बदलता रहा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी बेहद शातिर और योजनाबद्ध तरीके से अपराध करता था।

गुजरात का हंसलपुर प्रोजेक्ट बना वैश्विक बेंचमार्क: भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स में 10 वर्षों में दर्ज की 20 गुना वृद्धि

विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल परिवहन में रेल एक तेज़ी से उभरता हुआ माध्यम बन रहा है। सड़क, रेल और समुद्री परिवहन के बीच संतुलन बनाते हुए कई देश अब कम लागत, कम कार्बन उत्सर्जन और उच्च दक्षता के कारण रेल आधारित लॉजिस्टिक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत में भी यही परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करते हुए, भारतीय रेल (विशेषकर अहमदाबाद रेल मंडल) ने कारों के परिवहन में अपनी हिस्सेदारी पिछले एक दशक में 1% से बढ़ाकर 24% से अधिक कर दी है।

1. भारत में रेल से कार ट्रांसपोर्ट: एक दशक का तुलनात्मक विश्लेषण

भारत में पहले अधिकांश कारों का परिवहन सड़क मार्ग (ट्रकों) से होता था, लेकिन पिछले दस वर्षों में भारतीय रेलवे ने Rail-based Automobile Transport के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

2013 से पहले की स्थिति (लगभग 2010–2013)

- ▸▸ रेल हिस्सेदारी (Rail Share): लगभग 1% से 1.5%
- ▸▸ सड़क हिस्सेदारी (Road Share): लगभग 98%
- ▸▸ सालाना परिवहनः लगभग 40,000 – 60,000 कारें प्रति वर्ष।
- ▸▸ मुख्य बाधाएँः सीमित ऑटोमोबाइल वैगन, निजी रेलवे साइडिंग का अभाव और कंपनियों की ट्रकों पर निर्भरता। उस समय मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियाँ भी सड़क मार्ग को ही प्राथमिकता देती थीं।

वर्तमान स्थिति (2023–2025)

- ▸▸ रेल हिस्सेदारीः 20% से 24% तक।
- ▸▸ रेल से परिवहनः लगभग 10 लाख (1 मिलियन) से अधिक कारें प्रति वर्ष।
- ▸▸ वृद्धिः 2013 के मुकाबले लगभग 20 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि।
- ▸▸ विकास की समयरेखा (Growth Timeline)

वर्ष

- ▸▸ रेल हिस्सेदारी (Rail Share)
- ▸▸ रेल से परिवहन की गई कारें
- ▸▸ 2010
- ▸▸ ₹1%
- ▸▸ ₹40,000
- ▸▸ 2013
- ▸▸ ₹1.5%
- ▸▸ ₹60,000
- ▸▸ 2016
- ▸▸ ₹5%
- ▸▸ ₹1.5 लाख
- ▸▸ 2019
- ▸▸ ₹10%
- ▸▸ ₹3 लाख
- ▸▸ 2022
- ▸▸ ₹18%
- ▸▸ ₹7 लाख
- ▸▸ 2024–25
- ▸▸ ₹20–24%
- ▸▸ 10 लाख+
- ▸▸ इस अभूतपूर्व वृद्धि के मुख्य कारण

1.AFTO योजनाः 'ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर' योजना के तहत निजी कंपनियों को विशेष वैगन चलाने की अनुमति दी गई।

2.आधुनिक वैगन (NMGH & BCACBM): विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये वैगन एक ही ट्रेन में 250–300 कारों को ले जाने में सक्षम हैं।

3.इन-प्लांट साइडिंग्सः गुजरात (हंसलपुर), मानेसर और चेन्नई जैसे ऑटोमोबाइल हब में सीधे प्लांट तक रेलवे लाइन बिछाई गई।

4.किफायती एवं हरितः सड़क के मुकाबले रेल परिवहन 15–20% सस्ता है और इसमें 60–70% कम कार्बन उत्सर्जन होता है।

SIAM के अनुसारः भारत में हर साल लगभग 45–50 लाख कारों का उत्पादन होता है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक अपनी हिस्सेदारी को 35% तक ले जाना है।

गुजरात रेल प्रोजेक्टः अहमदाबाद रेल मंडल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेल मंडल के अंतर्गत हंसलपुर (गुजरात) स्थित प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट अब एक वैश्विक बेंचमार्क बन चुका है। यह प्रोजेक्ट 'Verra Carbon Standard' के तहत दुनिया का पहला "Modal Shift Transportation Project" घोषित हुआ है।

यह उपलब्धि अहमदाबाद मण्डल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है।

i. रेल आधारित लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा

गुजरात के हंसलपुर स्थित यह रेलवे साइडिंग अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत संचालित रेल नेटवर्क से जुड़ी है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में वाहनों का परिवहन रेल द्वारा संभव हुआ है, जिससे रेलवे की माल ढुलाई क्षमता, दक्षता एवं उपयोगिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ii. पर्यावरण संरक्षण में रेलवे की भूमिका मजबूत

- ▸▸ पर्यावरणीय लाभः इस परियोजना से लगभग 1.7 लाख टन CO उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।
- ▸▸ राजस्व वृद्धिः इससे अहमदाबाद मंडल के माल ढुलाई राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
- ▸▸ दक्षताः रेल परिवहन, सड़क की तुलना में 15–20% सस्ता तथा 60–70% कम कार्बन उत्सर्जन वाला माध्यम है।

iii. प्रधानमंत्री गति शक्ति एवं मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा

यह परियोजना PM GatiShakti के अंतर्गत विकसित मल्टी-मोडल अवसंरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें रेलवे लॉजिस्टिक्स की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों को तेज, सुगम और एकीकृत कनेक्टिविटी प्राप्त होती है।

iv. माल ढुलाई राजस्व एवं परिचालन दक्षता में वृद्धि

औद्योगिक रेलवे साइडिंग से—

- ▸▸ रेलवे के माल राजस्व (Freight Revenue) में वृद्धि होती है।
- ▸▸ सड़कों पर यातायात दबाव कम होता है।
- ▸▸ लॉजिस्टिक्स अधिक तेज, सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनता है।

v. अहमदाबाद मंडल के लिए मॉडल प्रोजेक्ट

यह परियोजना भविष्य में अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी। इससे अहमदाबाद रेल मंडल में और अधिक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल एवं रेलवे साइडिंग के विकास की संभावनाएं सुदृढ़ होंगी, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

3. नीतिगत सुधारः सफलता के मुख्य आधार

भारतीय रेलवे ने उद्योग के साथ सतत संवाद एवं AFTO (Automobile Freight Train Operator) योजना में महत्वपूर्ण सुधार किएः

- ▸▸ न्यूनतम शर्तों में राहतः रेक की न्यूनतम संख्या 3 से घटाकर 1 की गई तथा पंजीकरण शुल्क 5 करोड़ से घटाकर शून्य किया गया।
- ▸▸ आधुनिक वैगनः NMGH और BCACBM जैसे विशेष वैगनों की तैनाती, जो एक ट्रेन में 250–300 कारें ढो सकते हैं।

गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT): देशभर में 108 GCT कमीशन किए जा चुके हैं, जिनमें 8,049 करोड़ का निवेश हुआ है।

नए लोडिंग स्टेशनः चपानेर, चरोडी (WR), नासराला (NR), पेनुकोंडा (SWR) और पूर्वोत्तर (NFR) सहित कई नए स्टेशनों को जोड़ा गया।

2013 तक रेल की हिस्सेदारी केवल 1% थी, जो आज 20 गुना बढ़कर 24% से अधिक हो चुकी है। यह प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम और रेलवे की उद्योग-अनुकूल नीतियों का परिणाम है। अहमदाबाद रेल मंडल के लिए यह उपलब्धि न केवल राजस्व वृद्धि का प्रतीक है, बल्कि 'ग्रीन लॉजिस्टिक्स' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

सड़क से रेल की ओर यह 'मोडल शिफ्ट' आर्थिक रूप से लाभकारी होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। अहमदाबाद रेल मंडल के नेतृत्व में गुजरात के ऑटोमोबाइल हब अब वैश्विक स्तर पर 'ग्रीन लॉजिस्टिक्स' के मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।